ई-न्यूज

24 न्यूज अपडेट

WebSite.: https://24newsupdate.in

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

उदयपुर, शुक्रवार 03 जुलाई 2026

वर्ष 3 अंक 80

पृष्ठ 4

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: पहली बार बोला RSS, दोषियों को कठोर सजा की मांग; SIT जांच तेज



24 न्यूज अपडेट

अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पहली बार आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने शुक्रवार को वीडियो संदेश जारी कर कहा कि रामलला के दानपात्रों में जमा श्रद्धालुओं की राशि की चोरी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे करोड़ों रामभक्तों की आस्था और विश्वास को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। होसबाले ने कहा कि करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग और बलिदान से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट को वित्तीय प्रबंधन, संचालन व्यवस्था और पारदर्शिता को और मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा कायम रहे।

भाजपा नेता विनय कटियार का बयान

भाजपा नेता विनय कटियार ने कहा कि मामले में पैसों के गबन की बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों का नाम लेते हुए कहा कि वे अभी कार्रवाई से बचे हुए हैं और आगे जांच में स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने किसी के जेल जाने की बात नहीं कही थी।

SIT की जांच दूसरे दिन भी जारी

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी राम मंदिर परिसर पहुंची। सूत्रों के अनुसार टीम ने मामले से जुड़े ट्रस्ट सदस्य गोपाल राव से पूछताछ की। उधर, पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे की कस्टडी में लेकर पूछताछ की और उसके बाद उसे प्रतापगढ़ ले गई। पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि चढ़ावे में आए सोने-चांदी के आभूषण और नकदी अलग-अलग स्थानों पर ठिकाने लगाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस अविनाश को अयोध्या के कौशलपुरी स्थित योगा सेंटर भी लेकर पहुंची, जहां साक्ष्यों का सत्यापन किया गया।

आरोपी की निशानदेही पर ब्रेजा कार बरामद

पुलिस ने अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर अयोध्या से एक ब्रेजा कार (UP42 AP 6054) बरामद की है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस कार का इस्तेमाल कथित तौर पर नकदी के परिवहन में किया जाता था। बताया गया कि आरोपी ने यह कार करीब एक वर्ष पहले खरीदी थी। प्रतापगढ़ निवासी अविनाश शुक्ला राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के कार्य से जुड़ा था और अयोध्या में किराये के मकान में रहता था। पुलिस उसके कमरे से 20 लाख रुपये नकद, 1,000 अमेरिकी डॉलर, सोने-चांदी के आभूषण और 'रामराज्य कोष' लिखा एक बक्सा पहले ही बरामद कर चुकी है।

आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी

अयोध्या विकास प्राधिकरण (ADA) ने मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के मकानों को लेकर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम नोटिस जारी करने की बात कही है। वहीं, लवकुश की पत्नी का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और उनके मकान का नक्शा विधिवत स्वीकृत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की घोषणा की है। वहीं, केंद्रीय मंत्री संजय निषाद ने कहा कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच हो रही है और दोषियों को सजा मिल रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भी मामले की निष्पक्ष जांच कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने मंदिरों में चढ़ावे के पारदर्शी प्रबंधन और आभूषणों के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया।

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत पर रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने जमानत देने संबंधी मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल भी उठाए। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि शुरुआत में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने पर विचार किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान सोनम के वकील ने बताया कि वह पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं। ऐसे में अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार की याचिका पर सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार तय की है। अदालत ने कहा कि वह ट्रायल की प्रगति को भी ध्यान में रखेगी।

सरकार ने जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और सोनम को दोबारा हिरासत में भेजने की मांग की। उन्होंने कहा कि मामले के तथ्य बेहद गंभीर हैं और निचली अदालतों ने कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों एवं गवाहों पर पर्याप्त विचार नहीं किया। मेहता ने अदालत से कहा कि आरोपों की प्रकृति गंभीर है और जमानत देने से पहले सभी पहलुओं का समुचित परीक्षण किया जाना चाहिए।

बचाव पक्ष ने सहयोग का दिया भरोसा

सोनम रघुवंशी के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जमानत पर रोक लगाने का मतलब उनकी जमानत रद्द करना होगा, जबकि वह कोर्ट की शर्तों का पालन करते हुए शिलॉन्ग में ही मौजूद हैं। इस पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि यदि आरोपी पहले ही रिहा हो चुकी हैं तो इस स्तर पर जमानत पर रोक लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला ट्रायल के दौरान ही होगा। अदालत ने यह भी दोहराया कि जमानत देते समय तय कानूनी मानकों का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। सुनवाई के अंत में जस्टिस सुंदरेश ने हाल के कुछ चर्चित मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न पक्षों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने इस विषय पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि सोनम रघुवंशी पर पिछले वर्ष मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि सोनम पर साल 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने का मुख्य आरोप है. वह मई 2025 में अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय गए थे. यह जोड़ा 23 मई को नोंगरियत के एक होमस्टे से चेक-आउट करने के बाद लापता हो गया था. बाद में राजा का शव सोहरा में वेइसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई से बरामद किया गया था, जबकि सोनम का पता कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश में चला था.

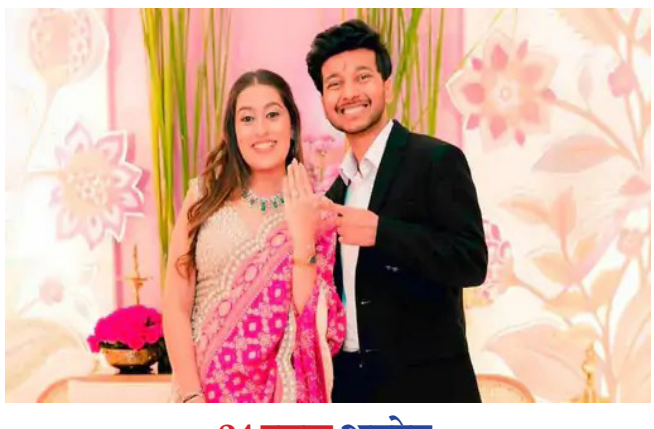
ई-रिक्शा चालकों के लिए राहत! सरकार ने बैटरी बंद करने वाले 3 ऐप हटाने के दिए आदेश



24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। देशभर में ई-रिक्शा चालकों के लिए परेशानी का कारण बने तीन मोबाइल ऐप्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आईटी मंत्रालय ने BAT-BMS, लॉसिजी और इपोच ली-आयन नाम के तीन ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, फिलहाल ये ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। हाल के दिनों में इन ऐप्स के जरिए चलते ई-रिक्शा की बैटरी बंद करने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं, जिसके बाद सरकार ने यह कार्रवाई की। दरअसल, कुछ ई-रिक्शा में लगी ब्लूटूथ सपोर्ट वाली लीथियम-आयन बैटरियों का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) बिना पासवर्ड या कमजोर सुरक्षा के साथ संचालित हो रहा था। इसका फायदा उठाकर कुछ लोग इन ऐप्स के जरिए 10 से 15 मीटर की दूरी से बैटरी से कनेक्ट हो जाते थे और चलते हुए ई-रिक्शा की बैटरी बंद कर देते थे। इस वजह से कई ई-रिक्शा बीच सड़क पर अचानक रुक गए। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए, जिससे ई-रिक्शा चालकों में दहशत फैल गई। विशेषज्ञों के अनुसार यह खतरा सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू नहीं होता। केवल उन्हीं ई-रिक्शा पर इसका असर पड़ सकता है, जिनमें ब्लूटूथ सपोर्ट वाली लीथियम-आयन बैटरी लगी हो और उसका ब्लूटूथ कनेक्शन बिना पासवर्ड या डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ खुला छोड़ दिया गया हो। वहीं लेड-एसिड बैटरी वाले ई-रिक्शा और मजबूत पासवर्ड से सुरक्षित बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले वाहन इस खतरे से पूरी तरह सुरक्षित हैं। BAT-BMS ऐप को मूल रूप से चीन की कंपनी शेन्जेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी ने बैटरी की मॉनिटरिंग के लिए विकसित किया था। इसका उपयोग बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान और हेल्थ की जानकारी देखने के लिए किया जाता है। यह ऐप सौर ऊर्जा उपकरणों, नावों और अन्य लीथियम बैटरी सिस्टम के रखरखाव के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग कर ई-रिक्शा की बैटरी को रिमोट से बंद करना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुरक्षा चूक के लिए स्थानीय स्तर पर बैटरी असेंबल करने वाले, कुछ डीलर्स और कम कीमत वाली लीथियम बैटरी बनाने वाले निर्माता भी जिम्मेदार हैं। कई बैटरियों में ब्लूटूथ मैनेजमेंट सिस्टम बिना पासवर्ड या बेहद आसान डिफॉल्ट पासवर्ड के साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से उससे कनेक्ट हो सकता है। ई-रिक्शा चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैटरी डीलर या अधिकृत मैकेनिक से संपर्क कर यह सुनिश्चित करें कि उनकी बैटरी का ब्लूटूथ सिस्टम पासवर्ड से सुरक्षित है। यदि बैटरी में 1234, 0000 या अन्य डिफॉल्ट पासवर्ड सेट है तो उसे तुरंत बदल दें। यदि चलते समय ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाए तो घबराने के बजाय वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बैटरी के मुख्य स्विच (MCB) को ऑफ कर दोबारा ऑन करें।

केतन अग्रवाल हत्याकांड: युवक हिरासत में, हत्या की साजिश की जानकारी पहले से थी, 'क्राइम पेट्रोल' देखकर बनाया प्लान



24 न्यूज अपडेट

पुणे। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जिले से एक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि वह बालेवाड़ी की एक कंपनी में काम करता है और सिया गोयल या मुख्य आरोपी चेतन चौधरी में से किसी एक का करीबी दोस्त है। जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर हत्या की साजिश की जानकारी पहले ही इस युवक के साथ साझा की थी। हालांकि पुलिस ने अभी उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, उसे मामले में गवाह बनाया जा सकता है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल ने वारदात से पहले टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' के कई एपिसोड देखे थे। जांच एजेंसियों का मानना है कि दोनों हत्या के बाद पुलिस जांच से बचने और सबूत छिपाने के तरीके समझने की कोशिश कर रहे थे। 18 जून को 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना गया था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस ने इसे सुनियोजित हत्या बताया। पुलिस का कहना है कि केतन, सिया और चेतन के रिश्ते में बाधा बन रहा था, इसलिए उसकी हत्या की साजिश रची गई।

इस बीच, पुणे की स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को दोनों मुख्य आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच के दौरान गुरुवार को पुलिस सिया गोयल को उसके लीलाकुंज स्थित घर लेकर पहुंची, जहां करीब 30 मिनट तक तलाशी ली गई। पुलिस ने घटना वाले दिन पहने गए कपड़े और कई डिजिटल सबूत जब्त किए। इसके बाद सिया को लुल्लानगर की उस पहाड़ी पर भी ले जाया गया, जहां पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कथित तौर पर वारदात की रिहर्सल की थी। मौके का पंचनामा तैयार कर क्राइम सीन रीक्रिएट किया गया।

उदयपुर के कई इलाकों में आज 7 घंटे बिजली बंद रहेगी, मेंटेनेंस के चलते रहेगा पावर शटडाउन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। शहर के कई क्षेत्रों में शुक्रवार (4 जुलाई) को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) ने आवश्यक मेंटेनेंस कार्य और लाइन शिफ्टिंग के चलते पावर शटडाउन की घोषणा की है। बिजली निगम के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करीब 7 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। शटडाउन के दौरान शक्तिनगर, देहलीगेट, एलआईसी बिल्डिंग क्षेत्र, एयर पैलेस, दुर्गा नर्सरी रोड, धबाई जी की बाड़ी, शिव पार्क कॉलोनी, अशोकनगर मेन रोड सहित आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली विभाग ने बताया कि विद्युत लाइनों के रखरखाव और आवश्यक तकनीकी कार्यों को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए यह शटडाउन लिया जा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली कटौती को देखते हुए अपने जरूरी कार्य पहले ही निपटा लें।

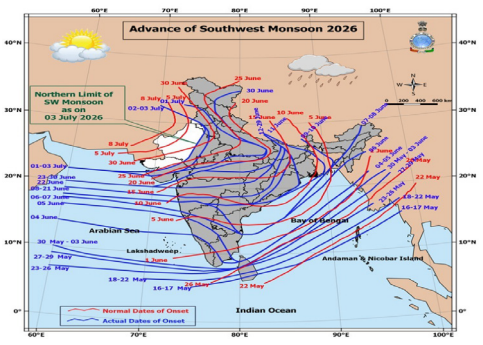
संपादकीय : शुचिता की राह

देश की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के मसले पर लंबे समय से बहस चलती रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, ताकि सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पांच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था इसमें कोई दोराय नहीं कि भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बढ़ता दखल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठा कर कई बार ऐसे लोग भी चुन कर संसद या विधानसभाओं में आ जाते हैं, जिन पर जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप होता है। अक्सर सामने आने वाली रिपोर्ट में खासी संख्या में दागी जनप्रतिनिधियों के विधायिका में पहुंचने का ब्योरा होता है, जिस पर सभी दल चिंता जताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट न देने को लेकर किसी के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखती। दूसरी ओर, चुनाव आयोग भी इस मसले पर कोई स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं करता है । इस लिहाज से देखें तो सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बाने से लेकर लोकतंत्र में नैतिकता और शुचिता सुनिश्चित किए जाने के लिए एक सख्त नियमन वक्त की जरूरत है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नया कानून देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर विपरीत प्रभाव डालने वाला न हो। दरअसल, विपक्षी दलों की ओर से प्रस्तावित कानून के प्रावधानों को अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया जा रहा है, जिसमें किसी आरोप के बाद दोषसिद्धि के बजाय सिर्फ हिरासत के आधार पर दंडित किए जाने की व्यवस्था है। आशंका यह जताई जा रही है कि सत्ताधारी दल की ओर से जांच एजंसियों का बेजा इस्तेमाल करके राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार कराया जा सकता है। ऐसे में चुनी हुई सरकारों के सामने भी अस्थिरता का संकट पैदा हो सकता है। जाहिर है, देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके।

अंतरिक्ष में कचरा

पृथ्वी की कक्षा में जिस रफ्तार से अंतरिक्ष कचरा बढ़ रहा है, इसका अनुमान उन देशों ने नहीं लगाया होगा जो संचार संबंधी जरूरतों और सामरिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्षों से उपग्रह भेजते रहे हैं। इन कचरों की वजह से पृथ्वी के लिए जोखिम पैदा होने की फिलहाल तो कोई आशंका नहीं है, लेकिन आने वाले वर्षों में अंदेशा नहीं गहराएगा, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल, अंतरिक्ष मलबे को साफ करने में न तो किसी की रुचि हैं और न ही इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कारगर साबित हुई है। खबरों के मुताबिक अंतरिक्ष में दस सेंटीमीटर से बड़े छत्तीस हजार टुकड़े तैर रहे हैं। जबकि इसके कणों की संख्या करोड़ों में है । इस पूरे मलबे का वजन तेरह हजार टन से अधिक है। विचित्र बात है कि तमाम देश सैन्य, संचार, कृषि, मौसम और सैन्य एवं खुफिया जानकारियों के लिए अंतरिक्ष में अपने उप्साह तो भेजते है, लेकिन मियाद खत्म होने के बाद उसके निपटान की कोई तैयारी नहीं करते। कचरे की समस्या इसी वजह से बढ़ी है। चिंता की बात यह कि कई निजी कंपनियां भी व्यावसायिक उपग्रह अंतरिक्ष भेज रही हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर उनके पास भी कोई योजना नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपना दबदबा कायम करना है नतीजा यह कि इस समय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रहों की संख्या पंद्रह हजार से अधिक हो चुकी है। इनमें दस हजार उपग्रह तो स्पेसएक्स कंपनी के हैं जो भविष्य में बड़ी संख्या में उपग्रह भेजने की योजना बना रही है। इससे आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष कचरे की संख्या बेतहाशा बढ़ेगी। ये इसलिए खतरनाक बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये सात किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहे हैं इस कचरे को निपटाने के तरीके सुरक्षित नहीं हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में धकेले जाने के बाद ये जल जरूर जाते हैं, लेकिन इससे कार्बन कण पैदा होने के कारण ओजोन परत पर असर पड़ता है। आखिरकार इसकी कीमत मनुष्यों को चुकानी पड़ेगी इस कचरे को साफ करने की ठोस योजना नहीं बनी तो अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक आशंका के बादल मंडराते रहेंगे ।

मेवाड़ में मानसून की दमदार एंट्री, सर्वाधिक बारिश बस्सी डेम पर, अगले 5-7 दिन भारी बारिश का अलर्ट



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। लंबे इंतजार के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार मेवाड़ में दस्तक दे दी है। मानसून सक्रिय होने के साथ ही उदयपुर संभाग में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 7 दिनों तक उदयपुर संभाग सहित दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार मानसूनी गतिविधियां लगातार सक्रिय रहेंगी और कई स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को मानसून ने उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़त दर्ज की। वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनूं जिलों से होकर गुजर रही है। विभाग का कहना है कि आगामी 3 से 4 दिनों में राज्य के शेष अधिकांश हिस्सों में भी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई हैं। इस वर्ष मानसून ने मेवाड़ में सामान्य से करीब आठ दिन की देरी से प्रवेश किया है। आमतौर पर उदयपुर क्षेत्र में मानसून 18 से 25 जून के बीच पहुंच जाता है, जबकि इस बार इसकी एंट्री 3 जुलाई को हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है और सितंबर के मध्य तक अच्छी बारिश की संभावना बनी रहती है।

बीते 24 घंटे में अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटे के दौरान मेवाड़ के कई क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग और वर्षामापी आंकड़ों के अनुसार' बस्सी डेम — 78 मिमी, ओराई डेम — 70 मिमी, गंभीरी डेम — 70 मिमी, निंबाहेड़ा — 70 मिमी, छोटीसादड़ी — 60 मिमी, रेलमगरा — 60 मिमी, कपासन — 54 मिमी। उदयपुर जिले में भी बारिश का अच्छा दौर रहा। जिले में सर्वाधिक ढाई इंच वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा एक इंच तक बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। जलाशयों में बढ़ेगी आवक, किसानों को राहत मानसून की सक्रियता से क्षेत्र के बांधों, जलाशयों और एनीकटों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद है। लगातार बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई को भी गति मिलेगी। किसान लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे थे और अब खेतों में कृषि गतिविधियां तेज होने की संभावना है। शहर और ग्रामीण इलाकों में बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

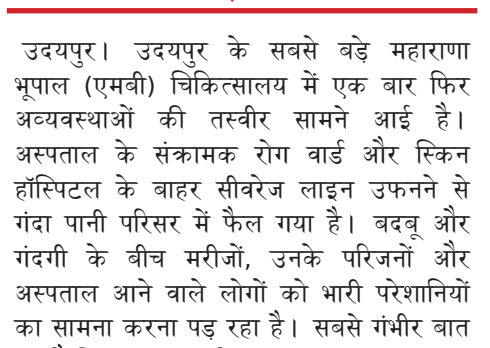
एमबी हॉस्पिटल में उफनता सीवरेज, बदबू और गंदगी के बीच इलाज को मजबूर मरीज



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भूपाल (एमबी) चिकित्सालय में एक बार फिर अव्यवस्थाओं की तस्वीर सामने आई है। अस्पताल के संक्रामक रोग वार्ड और स्किन हॉस्पिटल के बाहर सीवरेज लाइन उफनने से गंदा पानी परिसर में फैल गया है। बदबू और गंदगी के बीच मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इसी स्थान के पास अस्पताल का मुख्य नि:शुल्क दवा वितरण केंद्र संचालित होता है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीज दवाइयां लेने पहुंचते हैं। दवा वितरण केंद्र पर सुबह से शाम तक मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। लेकिन सीवरेज का गंदा पानी और उससे उठ रही तेज दुर्गंध के कारण लोगों को घंटों इसी अस्वच्छ वातावरण में खड़ा रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है। स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह सीवरेज संक्रामक रोग वार्ड के ठीक बाहर बह रहा है। ऐसे में गंदगी और दूषित पानी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ा सकता है। अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीजों के तीमारदारों व अस्पताल आने वालों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग से की जा चुकी है। शिकायतों के बाद कुछ बार सफाई कराकर औपचारिकता जरूर पूरी की गई, लेकिन सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया। नतीजतन कुछ ही दिनों बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीज पहले से ही बीमारी से जूझ रहे होते हैं, ऐसे में उन्हें बदबू, गंदगी और उफनते सीवरेज के बीच घंटों खड़ा रहना पड़ना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से तत्काल सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कर स्थायी समाधान करने की मांग की है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिल सके।

आधी रात सड़क पर लेपर्ड से सामना, कार रोककर बचाई जान; उदयपुर में फिर बढ़ी दहशत



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक बार फिर लेपर्ड की मौजूदगी से इलाके में दहशत फैल गई। गोगुंदा से दुकान बंद कर घर लौट रहे दो भाइयों के सामने अचानक सड़क किनारे लेपर्ड आ गया। दोनों भाइयों ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया और कुछ देर तक उसका वीडियो बनाया। कुछ मिनट बाद लेपर्ड जंगल की ओर चला गया। जानकारी के अनुसार, ढोल के बड़गांव निवासी शैलेश श्रीमाली अपने भाई नयन श्रीमाली के साथ गुरुवार रात करीब 12 बजे गोगुंदा से अपने गांव लौट रहे थे। नयन श्रीमाली की गोगुंदा में मोबाइल शॉप है। दोनों भाई उदयपुर से मोबाइल का सामान लेकर कार से वापस गांव जा रहे थे। जब वे नांदेशमा-ढोल मार्ग पर चामुंडा माता मंदिर से करीब 200 मीटर आगे पहुंचे, तभी सड़क किनारे पत्थर की दीवार पर एक लेपर्ड बैठा दिखाई दिया। अचानक सामने लेपर्ड को देखकर दोनों भाइयों ने घबराने के बजाय कार को सुरक्षित दूरी पर रोक दिया और मोबाइल से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ देर तक लेपर्ड दीवार पर बैठा रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लेपर्ड सड़क किनारे पत्थर की दीवार पर बैठा नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। शैलेश श्रीमाली ने बताया कि इस इलाके में यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार लेपर्ड दिखाई दे चुका है। खासकर रात के समय बाइक या अन्य वाहनों से गुजरने वाले लोगों को अक्सर लेपर्ड नजर आता है, जिससे ग्रामीणों और राहगीरों में लगातार भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लेपर्ड की लगातार आवाजाही के बावजूद वन विभाग की ओर से पर्याप्त निगरानी नहीं की जा रही है। उन्होंने वन विभाग से इलाके में नियमित गश्त बढ़ाने, लेपर्ड की गतिविधियों पर नजर रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

ग्रामीण सेवा शिविरों में पहुंचकर समस्याओं का समाधान कराएं: रणधीर सिंह भीण्डर



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य एवं पूर्व विधायक रणधीर सिंह भीण्डर ने शुक्रवार को वल्लभनगर पंचायत समिति की बालाथल, गोटीपा और धमाणियां पंचायतों का दौरा कर विभिन्न गांवों में आयोजित संपर्क सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीणों, किसानों और कार्यकर्ताओं से राजस्थान सरकार के ग्रामीण सेवा शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का समाधान कराने की अपील की। बडलिया में आयोजित बैठक में उन्होंने भूमि पैमाइश संबंधी त्रुटियां सुधारने और किसानों को अपनी भूमि का रिकॉर्ड अपडेट रखने की बात कही। बैठक की अध्यक्षता खेमराज डांगी ने की, जबकि रुपलाल मेनारिया ने भी संबोधित किया। धमाणियां में ग्रामीणों ने नालियों और अधूरी पुलिया की समस्या रखी, जबकि वाजमिया में पेयजल संकट और बडलिया में बिजली समस्या उठाई। भीण्डर ने संबंधित अधिकारियों एवं क्षेत्रीय सांसद से समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इस दौरान हरिसिंह सोनगरा, यशवंत सिंह झाला, पारस नागौरी, प्रभाशंकर शर्मा, नारायण लोहार, देवी सिंह और श्याम लाल जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रथम वर्ष में सीटें बढ़ाने की मांग, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने एसबीपी कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन



24 न्यूज अपडेट

डूंगरपुर। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने शुक्रवार को एसबीपी कॉलेज की विभिन्न छात्रहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य डॉ. गणेश लाल निनामा को ज्ञापन सौंपा। जिला संयोजक तुषार परमार के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में प्रथम वर्ष में सीटों और सेक्शन की संख्या बढ़ाने सहित विद्यार्थियों की अन्य मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। जिला मीडिया प्रभारी विजयपाल होता ने बताया कि संगठन ने कॉलेज आयुक्त, जयपुर के नाम संबोधित ज्ञापन में कहा कि प्रथम वर्ष में कला संकाय में 2100, बायोलॉजी में 264, गणित में 176 और कॉमर्स में 31 सीटों पर अंतिम प्रवेश हुए हैं। इसके बावजूद आदिवासी बहुल क्षेत्र होने और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की बड़ी संख्या सरकारी महाविद्यालय में प्रवेश की इच्छुक है, लेकिन सीमित सीटों के कारण कई विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। संगठन ने मांग की कि विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रथम वर्ष में नए सेक्शन शुरू किए जाएं और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना अधूरा न रह जाए। ज्ञापन में विषय आवंटन की समस्या भी उठाई गई। संगठन ने बताया कि अंतिम प्रवेश सूची में कई विद्यार्थियों को उनकी पसंद के बजाय अन्य विषय आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में प्राचार्य से चर्चा की गई, जिस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि महाविद्यालय स्तर पर विषय परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तथा इसकी तिथि दो दिन पहले जारी कर दी जाएगी। इस दौरान छात्रसंघ महासचिव निलेश रोत, पूर्व इकाई अध्यक्ष रवि परमार, इकाई अध्यक्ष लोकेश कटारा, संयुक्त संयोजक महेश कटारा, मीडिया प्रभारी देवेंद्र डामोर, जया ननोमा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

मेवलिया प्रजापति समाज मेवाड़ चौखला का शपथग्रहण एवं भामाशाह सम्मान समारोह 5 को

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मेवलिया प्रजापति समाज मेवाड़ चौखला की नवगठित कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह 5 जुलाई 2026 (रविवार) को सुबह 10 बजे रख्यावल स्थित नवनिर्मित श्रीयादे मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में समाज के पंचों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, युवाओं और समाजजनों की बड़ी संख्या में भागीदारी रहेगी। मेवाड़ चौखला के अध्यक्ष गणेश लाल प्रजापत (घासा) ने बताया कि समारोह में नवगठित कार्यकारिणी को विधिवत शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने मेवाड़ चौखला के सभी पंचों, समाज के वरिष्ठजनों, कार्यकारिणी सदस्यों और युवा साथियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। महामंत्री डीसी प्रजापत (बिठौली) ने बताया कि इस अवसर पर नवनिर्मित श्रीयादे मंदिर में विधि-विधान के साथ तस्वीर स्थापना की जाएगी। साथ ही मंदिर निर्माण में आर्थिक एवं अन्य सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान एवं स्वागत भी किया जाएगा। समारोह के उपरांत समाजजनों के लिए स्नेहभोज का आयोजन भी रखा गया है। यह स्नेहभोज प्रजापत परिवार, नउवा की ओर से आयोजित किया जाएगा। समाज के पदाधिकारियों ने सभी समाजबंधुओं से कार्यक्रम में शामिल होकर सामाजिक एकता और संगठन को मजबूत बनाने की अपील की है।

उदयपुर पुलिस ने करीब 5.97 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ नष्ट किए, 123 मामलों का माल किया डिस्पोज





24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ 97 लाख 49 हजार 790 रुपए मूल्य के जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन की अध्यक्षता में की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अंजना सुखवाल, पुलिस निरीक्षक (अपराध) प्रभुलाल और उनकी टीम की मौजूदगी में जिले के 23 पुलिस थानों के 123 प्रकरणों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को गुरुवार को डबोक स्थित सीमेंट फैक्ट्री में वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में 2,641.691 किलोग्राम डोडा चूरा, 317.244 किलोग्राम गांजा, 277.57 ग्राम एमडीएमए, 44.94 ग्राम ब्राउन शुगर, 542.400 लीटर कोडीन, 717.78 ग्राम चरस, 839.22 ग्राम नशीली दवाइयां तथा 106.443 किलोग्राम गांजे के पौधे शामिल हैं। कुल मिलाकर 3,609.658 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित बाजार कीमत 5.97 करोड़ रुपए से अधिक है। उदयपुर पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों का नियमानुसार नष्टीकरण किया जाता रहेगा।

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में वल्लभनगर बंद, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। वल्लभनगर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से कथित दुष्कर्म के मामले को लेकर शुक्रवार को वल्लभनगर कस्बा बंद रहा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखीं, जबकि ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीण वल्लभनगर-मावली मुख्य मार्ग पर धरने पर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। बाद में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जुलूस के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम रमेश चंद्र वडेरा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच, आरोपियों के खिलाफ शीघ्र चालान पेश करने तथा पीड़िता को जल्द न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग भी उठाई।

चार आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार

डीएसपी सरवन दास संत ने बताया कि करीब दो माह पहले नाबालिग के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि चार युवकों ने नाबालिग को विभिन्न प्रलोभन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा एक अन्य युवक पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है।

अजमेर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर 53 एटीवीएम फैसिलिटेटर नियुक्त होंगे



24 न्यूज अपडेट

रेलवे प्रशासन द्वारा अजमेर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम) से अनारक्षित टिकट जारी करने के लिए फैसिलिटेटरों की नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और सामान्य जनता से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, अजमेर मंडल श्री मिहिर देव के अनुसार इस योजना के तहत अजमेर मंडल के कुल 17 स्टेशनों पर 53 फैसिलिटेटरों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें अजमेर जंक्शन (07 पद), उदयपुर (06 पद), भीलवाड़ा (06 पद), आबू रोड (06 पद), पिंडवाड़ा (04 पद), मारवाड़ जंक्शन (03 पद), जवाई बांध (03 पद), मावली (02 पद), रानी (02 पद), डूंगरपुर (02 पद), राणाप्रताप नगर (02 पद), मदार (02 पद), सोमेसर (02 पद), कपासन (02 पद), फतेहनगर (02 पद), फालना (01 पद) और ब्यावर (01 पद) शामिल है। इस नियुक्ति की महत्वपूर्ण शर्तों और नियमों के अंतर्गत यह नियुक्ति पूरी तरह अनुबंध के आधार पर दो वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकतानुसार आगे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। रेलवे द्वारा कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि फैसिलिटेटर को टिकट बिक्री के मूल्य पर नियमानुसार 3% कमीशन दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में पहली प्राथमिकता सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को, दूसरी उनके नामित जीवनसाथी/ वयस्क संतान को और तीसरी सामान्य जनता को दी जाएगी। यदि किसी स्टेशन पर आवश्यकता से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो चयन पारदर्शी तरीके से लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) द्वारा किया जाएगा। सामान्य जनता से चुने गए फैसिलिटेटरों को एनएसजी-1 तथा एनएसजी-2 श्रेणी के स्टेशनों (अजमेर व उदयपुर) के लिए 50,000 तथा अन्य स्टेशनों के लिए 25,000** की रिफंडेबल सुरक्षा राशि (एफडीआर के रूप में) जमा करानी होगी। सामान्य जनता हेतु- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, वह उसी जिले का निवासी हो जहाँ का स्टेशन है, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक/ एसएसएलसी (10वीं) या समकक्ष होनी चाहिए। आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म और विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट WWW.NWR.INDIANRAILWAYS.GOV.IN पर दिनांक 03.07.2026 से उपलब्ध है।

पेट्रोल पंप पर युवक पर चाकू से हमले का प्रयास, CCTV में कैद हुई वारदात



24 न्यूज अपडेट

चित्तौड़गढ़। शहर के एक पेट्रोल पंप पर देर रात स्कूटी में पेट्रोल भरवाने पहुंचे युवक पर दो युवकों ने कथित तौर पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया। युवक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

पेट्रोल भरवाने पहुंचा, युवकों ने मांगे पैसे

करजाली निवासी युवक ने शिकायत में बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे वह स्कूटी से गांव लौट रहा था। रास्ते में शहर के बोकड़िया पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुका। स्कूटी खड़ी कर वह कुछ देर के लिए बाथरूम गया। लौटने पर स्प्लेंडर बाइक से आए दो युवकों ने उससे पैसे मांगे। जब उसने उन्हें पहचानने से इनकार करते हुए पैसे देने से मना किया तो दोनों उससे उलझ गए।

धारदार हथियार लेकर दौड़े, चाकू फेंका

पीड़ित के अनुसार, विवाद बढ़ने पर दोनों युवकों ने कमर से धारदार हथियार निकाल लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए वह पेट्रोल पंप की तरफ भागा, लेकिन आरोपी उसका पीछा करते रहे। इसी दौरान एक युवक ने उसकी ओर चाकू फेंका, जिससे वह बाल-बाल बच गया। शोर सुनकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। युवक का कहना है कि कर्मचारियों के समय पर पहुंचने से उसकी जान बच गई।

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

पीड़ित ने बताया कि पूरी वारदात पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। बाद में जानकारी जुटाने पर उसे पता चला कि आरोपियों में से एक हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि दूसरे की पहचान नहीं हो सकी। शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज के फोटो भी पुलिस को सौंपे गए हैं। युवक का आरोप है कि दोनों आरोपी पेट्रोल पंप के पीछे वाले रास्ते से आए थे और उनका इरादा लूट या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने का था।

राजस्थान में तबादलों की अवधि 10 जुलाई तक बढ़ी, सरकार ने दिए नए आदेश

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर दी गई छूट की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। अब विभिन्न विभागों में 10 जुलाई 2026 तक तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले सरकार ने 19 जून को तबादलों से प्रतिबंध हटाते हुए 5 जुलाई तक छूट दी थी। सरकार के अनुसार 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं भाजपा विधायक और संगठन के कई नेताओं ने भी छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया। तबादलों को लेकर इन दिनों मंत्रियों के आवास, भाजपा नेताओं के निवास और सचिवालय में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेशभर से सरकारी कर्मचारी तबादलों के लिए सिफारिशें करवाने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मांग शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और अन्य जनसंपर्क वाले विभागों में तबादलों की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों की प्राथमिकता पहले की तरह ही रहेगी। एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता तथा कैंसर, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश सरकारी विभागों के साथ-साथ निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। हालांकि, ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर वर्ष 2018 से लगी रोक इस बार भी नहीं हटाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए तबादलों पर लगी रोक बरकरार रखी गई है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सुखेर थाना क्षेत्र में एक महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धोखाधड़ी से रुपये ऐंठने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार एफआईआर में शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धोखे से उससे रुपये भी ऐंठ लिए। मामले में आरोपी की पहचान भगवान सहाय पुत्र प्रेमदयाल, निवासी हिण्डौन सिटी (करौली), हाल निवासी हेल्थ केयर सेंटर एवं श्री अंबिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर, भुवाणा के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सुखेर थाना प्रभारी भरत योगी कर रहे हैं।

सेवाश्रम पुलिया से रिटायर्ड बैंक मैनेजर की बाइक चोरी

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भूपालपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोर रिटायर्ड बैंक मैनेजर की बाइक चोरी कर ले गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता गणपतलाल भादवीया (71), निवासी डी-24, आदर्श नगर, उदयपुर ने रिपोर्ट में बताया कि 30 जून को सेवाश्रम पुलिया क्षेत्र से उनकी बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। मामले की रिपोर्ट 2 जुलाई को भूपालपुरा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने सहित जांच शुरू कर दी है।

नाकाबंदी देख शराब तस्कर कार छोड़ भागा, 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर दी गई छूट की अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। अब विभिन्न विभागों में 10 जुलाई 2026 तक तबादले किए जा सकेंगे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले सरकार ने 19 जून को तबादलों से प्रतिबंध हटाते हुए 5 जुलाई तक छूट दी थी। सरकार के अनुसार 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। वहीं भाजपा विधायक और संगठन के कई नेताओं ने भी छूट की अवधि बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया। तबादलों को लेकर इन दिनों मंत्रियों के आवास, भाजपा नेताओं के निवास और सचिवालय में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रदेशभर से सरकारी कर्मचारी तबादलों के लिए सिफारिशें करवाने पहुंच रहे हैं। सबसे अधिक मांग शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और अन्य जनसंपर्क वाले विभागों में तबादलों की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों की प्राथमिकता पहले की तरह ही रहेगी। एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता तथा कैंसर, हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश सरकारी विभागों के साथ-साथ निगम, बोर्ड और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा। हालांकि, ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर वर्ष 2018 से लगी रोक इस बार भी नहीं हटाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए तबादलों पर लगी रोक बरकरार रखी गई है।

एनएचएम में लघु एवं सीमांत किसान बनकर कटारिया ने ग्रीन हाउस पर ले ली 17.04 लाख की सब्सिडी!! भाजपा नेता डॉ. विप्लवी का आरोप, पीएम मोदी से उच्चस्तरीय जांच की मांग

24 न्यूज अपडेट



उदयपुर। भाजपा नेता, अधिवक्ता एवं पूर्व पार्षद डॉ. विजय विप्लवी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया पर अबकी बार खोजी पत्रकार बनकर एक और मारक प्रहार किया है। विप्लवी ने कटारिया पर राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत स्वयं को लघु एवं सीमांत किसान दर्शाकर नियम विरुद्ध सरकारी अनुदान (सब्सिडी) लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को विस्तृत पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

डॉ. विप्लवी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के वेलनिया गांव स्थित राज्यपाल कटारिया के फार्म हाउस पर वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत लगभग 22 लाख 12 हजार 358 रुपये की लागत से ग्रीन हाउस स्थापित किया गया। उनके अनुसार इस परियोजना पर 17 लाख 4 हजार 528 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया, जो कुल लागत का लगभग 77.04 प्रतिशत है। उनका आरोप है कि यह योजना में निर्धारित अधिकतम अनुदान सीमा से करीब 7.5 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि राजस्थान सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्रीन हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50 प्रतिशत, जबकि लघु एवं सीमांत किसान तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को अधिकतम 70 प्रतिशत तक ही अनुदान दिया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया कि सामान्य वर्ग से आने वाले राज्यपाल कटारिया को लघु एवं सीमांत किसान की श्रेणी में किस आधार पर रखा गया और उन्हें अधिकतम सीमा से अधिक अनुदान कैसे स्वीकृत किया गया।

डॉ. विप्लवी ने दावा किया कि वेलनिया स्थित कटारिया का फार्म हाउस करीब 33 बीघा भूमि पर विकसित है, जहां दो सुविधायुक्त आवासीय परिसर, दो कुएं तथा चारदीवारी और कंटीले तारों की फेंसिंग है। इसके अलावा मूणवास, कैलाशपुरी सहित अन्य स्थानों पर भी उनके स्वामित्व में कृषि भूमि होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे में उन्हें किसी भी मानक के अनुसार लघु या सीमांत किसान नहीं माना जा सकता। उन्होंने राज्यपाल को जारी लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण-पत्र की वैधता की भी जांच कराने की मांग की है।

पत्र में उन्होंने यह भी लिखा कि कटारिया पेशे से किसान नहीं, बल्कि शिक्षक, अधिवक्ता, राजनेता और वर्तमान में राज्यपाल हैं। उन्होंने प्रश्न उठाया कि लगभग 82 वर्ष की आयु, पांच दशक के राजनीतिक जीवन, करीब 39 वर्ष जनप्रतिनिधि और लगभग 29 वर्ष कैबिनेट मंत्री स्तर की सुविधाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद पर रहते हुए अचानक लघु एवं सीमांत किसान कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने इसे आश्चर्यजनक और जांच का विषय बताया।

डॉ. विप्लवी ने यह भी आरोप लगाया कि ग्रीन हाउस पर लगे सूचना पट्ट पर "लघु कृषक" के रूप में गुलाबचंद कटारिया का नाम अंकित है। उन्होंने कहा कि जब देश में वास्तविक छोटे और जरूरतमंद किसान सरकारी सहायता के पात्र हैं, तब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी सब्सिडी लेना जनता के बीच गलत संदेश देता है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री के आह्वान पर करोड़ों लोगों ने रसोई गैस सब्सिडी का स्वेच्छा से त्याग किया, वहीं दूसरी ओर यदि कोई राज्यपाल नियमों के विपरीत सरकारी अनुदान प्राप्त करता है तो यह गंभीर चिंता का विषय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

डॉ. विप्लवी ने अपने पत्र में राज्यपाल कटारिया से जुड़े पूर्व के कई विवादों का भी उल्लेख किया है। इनमें उदयपुर के बड़ी क्षेत्र में वन भूमि प्रकरण, मूणवास में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प ड्यूटी बचाने का आरोप, कोरोना लॉकडाउन के दौरान झाड़ोल जाकर भूमि की रजिस्ट्री कराना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चार मकानों का आउट ऑफ टर्न आवंटन तथा पंजाब के राज्यपाल रहते हुए उदयपुर के सर्किट हाउस में नियमित जनसुनवाई करने जैसे मामलों का हवाला दिया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए इन तथ्यों की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

पत्र के अंत में डॉ. विप्लवी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जिम्मेदार लोग 'अंत्योदय' के बजाय 'स्वोदय' की भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने लगेंगे तो योजनाओं का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को जारी लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण-पत्र की जांच कराई जाए। साथ ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि जांच में उन्हें वास्तव में लघु एवं सीमांत किसान पाया जाता है तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन नियम, 2019 के तहत उन्हें पेंशन का लाभ भी दिलाने पर विचार किया जाना चाहिए।

नोट: यह समाचार भाजपा नेता डॉ. विजय विप्लवी द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र और उसमें लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों पर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया अथवा संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। समाचार में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। उनका पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

दो दिवसीय नि:शुल्क रोग निवारण शिविर, प्राकृतिक चिकित्सा पर मिलेगा विशेषज्ञों का परामर्श

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 3 जुलाई। श्री लाइफ गुरुकुलम एवं श्री लाइफ वेलनेस के संयुक्त तत्वावधान में, अंतर्राष्ट्रीय गुर्जरगौड़ महासभा के सहयोग और लाइफ कोच योगी तनुज बावागुरु की प्रेरणा से शनिवार से दो दिवसीय नि:शुल्क रोग निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ सुबह 9 बजे शोभागपुरा स्थित भगवत रत्न भवन (महावीर कॉम्प्लेक्स, एसबीआई बैंक के पीछे, 100 फीट रोड) में होगा। शिविर में हृदय रोग, सर्वाइकल, साइनस, रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, लीवर संबंधी रोग, लकवा, मधुमेह, माइग्रेन, घुटनों का दर्द और उच्च रक्तचाप सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर नि:शुल्क जांच एवं परामर्श दिया जाएगा। आयोजन सचिव डॉ. पंकज उपाध्याय ने बताया कि शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार और जीवनशैली सुधार संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जांच बिना सुई, एक्स-रे, एमआरआई या सीटी स्कैन के की जाएगी। शिविर में दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों से आए आयुर्वेद एवं एडवांस अल्टरनेटिव थेरेपी के विशेषज्ञ मास्टर ट्रेनर जीवन सिंह सोलंकी और उनकी टीम सेवाएं देंगी। साथ ही नि:शुल्क परामर्श, दर्द निवारण चिकित्सा और स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी मार्गदर्शन भी उपलब्ध रहेगा। श्री लाइफ फाउंडेशन की संस्थापक शशि शर्मा ने बताया कि शिविर के बाद नियमित उपचार एवं प्रशिक्षण सेवाएं श्री लाइफ वेलनेस एवं वैदिक थेरेपी केंद्र, सरल ब्लड बैंक के पास, भूपालपुरा मठ, उदयपुर में उपलब्ध रहेंगी। केंद्र का उद्घाटन कालका माता मंदिर के पुजारी देवेन्द्र सिंह गौड़ और मंजू देवी जोशी करेंगे। वहीं, शिविर का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय गुर्जरगौड़ महासभा के जिलाध्यक्ष रंजनराज आचार्य और सरला देवी जोशी के मुख्य आतिथ्य में होगा। डॉ. हेमंत जोशी के सानिध्य में संचालित होने वाले इस केंद्र का उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराने और बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक करना बताया गया है।

आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की हड़ताल की चेतावनी, 6 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन; दवा वितरण सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय (एमबी हॉस्पिटल) और सुपर स्पेशलिटी विभाग में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत कार्यरत ठेका फार्मासिस्टों, सहायक कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को ओपीडी के बाहर दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे सोमवार, 6 जुलाई 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे अस्पताल की दवा वितरण और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि संबंधित ठेका फर्म उनकी पीएफ (Provident Fund) और ईएसआई (Employee State Insurance) की राशि वेतन से काट रही है, लेकिन उसे समय पर संबंधित खातों में जमा नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उन्हें नियत तिथि पर वेतन भी नहीं मिल रहा, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सहायक कर्मचारियों ने भी प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना है कि समान कार्य और समान पद होने के बावजूद उन्हें अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है, जबकि प्रदेश के अन्य अस्पतालों में इसी योजना के कर्मचारियों को कुशल श्रमिक का दर्जा और उसी के अनुरूप वेतन व सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों का शीघ्र समाधान नहीं होने तक उनका धरना जारी रहेगा। यदि प्रशासन ने समय रहते पहल नहीं की तो 6 जुलाई से शुरू होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना सहित कई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हड़ताल के कारण मरीजों को होने वाली किसी भी असुविधा और उससे उत्पन्न परिस्थितियों की पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और संबंधित ठेका फर्म की होगी। कर्मचारियों ने प्रशासन से तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों का समाधान करने की मांग की है, ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

कृषि छात्राओं के लिए खुशखबरी: प्रोत्साहन राशि के आवेदन शुरू, 31 जनवरी 2027 तक करें अप्लाई

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 3 जुलाई। राज्य सरकार ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2026-27 में कृषि विषय की छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने हेतु राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र छात्राएं 1 जुलाई 2026 से 31 जनवरी 2027 तक आवेदन कर सकेंगी। कृषि आयुक्तालय ने सभी जिला परिषदों के संयुक्त निदेशक (कृषि) को निर्देश दिए हैं कि वे जिले के कृषि विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को योजना की जानकारी दें, ताकि अधिक से अधिक छात्राएं इसका लाभ उठा सकें। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि 31 जनवरी 2027 के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने संस्था प्रमुखों से आवेदन के दौरान छात्राओं के अध्ययनरत वर्ष की सही जानकारी दर्ज कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर और बिना किसी त्रुटि के किया जा सके।

इतनी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

11वीं एवं 12वीं (कृषि): 15,000 प्रतिवर्ष
बीएससी (कृषि): 25,000 प्रतिवर्ष
एमएससी (कृषि): 25,000 प्रतिवर्ष
पीएचडी (कृषि): 40,000 प्रतिवर्ष

पिछले वर्ष 35 हजार छात्राओं को मिला लाभ

वर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष इस योजना के तहत उदयपुर जिले की करीब 1,350 छात्राओं को 3.5 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई थी। वहीं, राज्यभर में लगभग 35 हजार छात्राओं को 70 करोड़ रुपये का लाभ मिला।

पूर्व अध्यक्ष की प्रथम पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण, मेनारिया समाज ने दी श्रद्धांजलि



24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 3 जुलाई। मेनारिया समाज ग्राम सभा, पानेरियों की मादड़ी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बद्रीलाल कचरावत की प्रथम पुण्यतिथि पर गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम निरंजन राष्ट्रीय व्यायामशाला, बजरंग क्लब एवं मेनारिया समाज ग्राम सभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय बद्रीलाल कचरावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर तथा दो मिनट का मौन रखकर की गई। इस दौरान समाजजनों ने उनके समाजसेवा, संगठनात्मक कार्यों और जनकल्याण के प्रति योगदान को याद करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए।

समाज के प्रवक्ता कैलाश मेनारिया ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से बावड़ी वाले हनुमानजी मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में मेनारिया समाज ग्राम सभा के पदाधिकारी, वरिष्ठजन, युवा एवं समाज के अनेक गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, विधायक चेतर भाई वसावा को न्याय दिलाने की मांग

24 न्यूज अपडेट



सलूम्बर। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के जिला अध्यक्ष आनंद कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गुजरात के डेडियापाड़ा से विधायक चेतर भाई वसावा के खिलाफ दर्ज प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विधायक चेतर भाई वसावा, उनकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ वन विभाग ने राजनीतिक साजिश के तहत गलत तरीके से मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। ज्ञापन में इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आदिवासियों के परंपरागत भूमि अधिकारों और वन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत उचित हस्तक्षेप कर विधायक वसावा को न्याय दिलाने की मांग की गई। ज्ञापन में अनुसूचित क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम-2006 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से पूरे मामले की समीक्षा कर आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

आचार्य पुलकसागरजी महाराज का वंडर सीमेंट में भव्य मंगल प्रवेश!

परिवार की सादगी और धार्मिक प्रवृति देखकर अभिभूत हुआ हूँ - आचार्य पुलकसागर



24 न्यूज अपडेट

निम्बाहेड़ा/ वंडर सीमेंट लिमिटेड परिसर में शुक्रवार को आचार्य श्री 108 पुष्पदन्त सागरजी महाराज के परम शिष्य आचार्य श्री पुलकसागरजी महाराज का ससंघ भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर वंडर सीमेंट के वाईस चेयरमैन विमल पाटनी, श्रीमती तारिका पाटनी सहित पाटनी परिवार तथा आर.के. मार्बल के निर्मल दोषी, वंडर सीमेंट के निदेशक परमानन्द पाटीदार एवं यूनिट हेड नितिन जैन* सहित अधिकारियों ने विधिवत स्वागत किया और मुनि श्री के पद प्रक्षालन कर धर्म के प्रति अपनी निष्ठा जताई! अपने मंगल प्रवचन में आचार्यश्री ने गुरु भक्ति, सेवा, त्याग, विनम्रता और समाज के प्रति समर्पण का संदेश देते हुए कहा कि "मैं वंडर सीमेंट में आर.के. परिवार की सादगी, अपनापन और संतों के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत अभिभूत हूँ।" उन्होंने समाज रत्न अशोक पाटनी के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि वैभव के साथ त्याग और समाजहित का ऐसा समन्वय अत्यंत प्रेरणादायी है। वंडर समूह के कार्यों कि प्रशंसा करते हुए आगे मुनि श्री ने कहा कि सीमेंट जोड़े ईंट को, धर्म जोड़े जीव को, झुका जो शीश गुरु चरण, उसने जीता जग को,सोच बना वंडर जैसी, व्यक्तित्व

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक -सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा।